JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

अर्थव्यवस्था में नकदी रहित लेनदेन को प्रेरित करने वाली शक्तियाँ

डॉ. प्रकाश सीरवी
सह आचार्य अर्थशास्त्र
एस.पी.सी. राजकीय महाविद्यालय
अजमेर (राजस्थान)

सारांश

किसी भी देश को सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसकी वित्तीय व्यवस्था मजबूत हो और वित्तीय व्यवस्था तभी मजबूत हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति उससे जुड़ा हो। हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जहाँ अधिकतर लेनदेन नकद में होता है, परन्तु 2016 में मोदी सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के उपरान्त अधिकतर लेनदेन नकदी रहित होने लगा इसे गति देने का कार्य, डिजिटल लेनदेन ने किया। ऐसे लेनदेन में पारदर्शिता होती है व जनकल्याण में वृद्धि होती है, साथ ही वित्तीय व्यवस्था में भी मजबूती आती है। परन्तु भारत जैसे देश में साक्षरता की कमी व डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण लोग डिजिटल माध्यमों से लेनदेन करने में हिचकिचाते हैं, साइबर खतरों ने भी नकदी रहित लेनदेन को प्रभावित किया है। परन्तु एक और इस प्रकार के लेनदेन से सरकार के कर संग्रह में बढ़ोतरी व महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा जैसे अवसर भी उपलब्ध कराए हैं।

संकेत शब्द :– डिजिटल भुगतान, नकदी रहित अर्थव्यवस्था, विमुद्रीकरण, वित्तीय समावेशन, त्वरित भुगतान।

प्रस्तावना :–

वर्तमान युग नवाचारों का है। भारत ने भी संचार प्रौद्योगिकी में नई तकनीक का प्रयोग करते हुए डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया है। नकदी रहित लेनदेन से देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। अर्थव्यवस्था में नकदी रहित लेनदेन को प्रेरित करने में अनेक शक्तियाँ आन्तरिक व बाह्य रूप से योगदान दे रही हैं। किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए उस देश की वित्तीय व्यवस्था मजबूत होना अत्यावश्यक है और इस व्यवस्था को गति प्रदान करने का कार्य डिजिटल लेनदेन ने किया है। नगदी रहित

लेनदेन से सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचा रही है। अर्थात् सरकारी योजनाओं के संचालन में कुशलता व पारदर्शिता में वृद्धि होती है और त्वरित भुगतान होता है। परन्तु भारत जैसे देश में आधारभूत संरचना की कमी, नेटवर्क कनेक्टिविटी में बाधा और साइबर खतरों ने डिजिटल भुगतान को काफी मात्रा में प्रभावित किया है लेकिन डिजिटल भुगतान से कर संग्रह में बढ़ोतरी समाज को सशक्त करने व संकट के समय में शीघ्र भुगतान जैसे अवसर भी प्रदान किए हैं।

साहित्य पुनरावलोकन :–

पवनीत कौर (2019) "कैश टू कैशलेस इकोनोमी : चैलेंज एण्ड ओपरचुनिटी" में अपने लेख में नकदी रहित अर्थव्यवस्था के अवसर व चुनौतियाँ का अध्ययन किया है और बताया कि भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि इससे मुद्रा की छपाई और रखरखाव पर खर्च की जाने वाली राशि की भारी बचत होगी।

दिक्षा आहूजा (2018) ने अपने अध्ययन 'कैशलेस इकोनोमी इन इंडिया' में कैशलेस अर्थव्यवस्था की शक्तियों, कमजोरियों उसके अवसर व चुनौतियों का अध्ययन किया है, और यह निष्कर्ष निकाला कि यह अवधारणा विश्वसनीय और उत्कृष्ट है। भारतीयों को इस अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए।

शोध पत्र का उद्देश्य :–

- नकदी रहित अर्थव्यवस्था के महत्व का अध्ययन।
- नकद रहित अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने वाली शक्तियों का अध्ययन।
- नकदी रहित अर्थव्यवस्था के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का अध्ययन।
- नकदी रहित अर्थव्यवस्था में अवसरों की तलाश का अध्ययन।

नकदी रहित अर्थव्यवस्था का महत्व :–

वर्तमान में नकदी रहित लेनदेन का महत्व दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि यह सरल व सुरक्षित है, इससे लेनदेन में पारदर्शिता होती है जिससे करवंचन में कमी व कर संग्रह मे आसानी होती है इससे आर्थिक विकास को गति मिलती है क्योंकि सरकार द्वारा इससे शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार जैसी आधारभूत सुविधाओं पर खर्च बढ़ता है जिससे जनकल्याण में वृद्धि होती है। नकदी रहित लेनदेन का महत्व कोविड–19 जैसी महामारी के दौरान और बढ़ गया। उस वक्त इस प्रकार के लेनदेन से ही अर्थव्यवस्था चलायमान थी। आर.बी.आई. के अनुसार लॉकडाऊन के दौरान लगभग एक तिहाई परिवार ऐसे थे जिन्होंने

पहली बार डिजिटल रूप से लेनदेन किया। अतः नकदी रहित लेनदेन व्यक्ति व सरकार दोनों के लिए लाभदायक है।

अर्थव्यवस्था में नकदी रहित लेनदेन को प्रेरित करने वाली शक्तियाँ

वित्तीय समावेशन :–

वित्तीय समावेशन का अर्थ वहन योग्य मूल्य पर समाज के पिछड़े व कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने से हैं। भारत में वित्तीय समावेशन स्वतंत्रता के बाद 1956 में जीवन बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के साथ ही शुरू हुआ इसके बाद कई पहल की गई। हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में जनधन योजना की शुरूआत की गई, जिसके तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जीरो बैलेंस पर बैंक में खाते खोले गए जिससे लोग वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बने। पीएमजेडीवाई के तहत 30 जनवरी 2019 तक 3401 करोड़ खाते खोले गए जिनमें 89257 करोड़ रूपये जमा किए गए। परन्तु इस व्यवस्था को गति देने का कार्य डिजिटल लेनदेन ने किया।

सरकारी योजना के संचालन में कुशलता :–

भारत सरकार ने 1950 के दशक से ही गरीब व असहाय लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई प्रयास किए हैं व वर्तमान में भी कर रही है। इसके लिए कई योजनाओं का निर्माण किया गया, जैसे–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अन्तोदय योजना, गरीब कल्याण योजना, मनरेगा इत्यादि परन्तु इन योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ बिचौलियों के कारण लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन नकदी रहित लेनदेन से गरीब व असहाय लोगों के लिए बनाई योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचता है इससे बिचौलियों का अन्त होता है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

पारदर्शिता में वृद्धि :–

पारदर्शिता किसी भी अर्थव्यवस्था को कुशल बनाने का महत्वपूर्ण गुण है। मुद्रा के नकद लेनदेन से इसके बारे में विवरण प्राप्त करना मुश्किल होता है, जो करवंचन व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, परन्तु मुद्रा के नकद रहित लेनदेन जो डिजिटल माध्यमों एन.ई.एफ.टी., आर.टी.जी.एस., यू.पी.आई. व आई.एम.पी.एस. के द्वारा किया जाता है। इससे लेनदेन का विवरण प्राप्त करना आसान होता है, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

जाली मुद्रा पर अंकुश :–

डिजिटल माध्यमों से लेनदेन करने पर भौतिक मुद्रा की मांग में कमी आयेगी जो भौतिक मुद्रा की पूर्ति में कमी लायेगी, जिससे मुद्रा के जाली निर्माण पर अंकुश लगेगा। इससे होने वाले भ्रष्टाचार, चोरी,

डकैती, तस्करी व आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण पर रोक लगेगी, जो इन गतिविधियों को हतोत्साहित करेगी।

नकदी रहित लेनदेन के क्रियान्वयन में बाधाएँ :–

साक्षरता की कमी :–

भारत एक पूर्ण साक्षर देश नहीं है, भारत की साक्षरता दर 74.4 प्रतिशत है जो काफी कम है, इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 67.77 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रों में 84.11 प्रतिशत हैं। साथ ही जो पढ़े–लिखे हैं उनमें भी डिजिटल साक्षरता की कमी है जिससे अधिकतर लोग डिजिटल माध्यमों से लेनदेन करने से हिचकिचाते हैं। जिसके कारण भारत में नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में सरकार द्वारा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। इस नीति में डिजिटल माध्यमों के प्रयोग को प्राथमिकता दी गई है।

आधारभूत संरचना की कमी :–

नकदी रहित लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाता है जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर व पी.ओ.एस. इत्यादि इन साधनों के संचालन के लिए बिजली की उपलब्धता अति आवश्यक है, अतः भारत में अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता नहीं है। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2016–17 के अनुसार आपूर्ति बिजली की गुणवत्ता के संदर्भ में भारत का स्थान 138 देशों में 88वाँ है।

नेटवर्क कनेक्टीविटी व इन्टरनेट की लागत :–

नकदी रहित लेनदेन के लिए बिजली के साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी व इन्टरनेट की भी आवश्यकता होती है। हालांकि इन्टरनेट और ब्राडबैंड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से प्रवेश किया। इन्टरनेट उपभोक्ताओं की संख्या ब्राडबेंड तथा नेरोबैंड की संख्या मार्च 2019 में 636.73 मिलियन की तुलना में सितम्बर 2020 के अन्त तक 776.45 मिलीयन पहुँच गई, लेकिन जहाँ भारत में कुल टेली घनत्व 2020 के अन्त तक 86.37 प्रतिशत पर था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीघनत्व 58.85 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 138.97 प्रतिशत है। इनमें व्यापक अन्तर है, अतः इस खाई को पाटना आवश्यक है ताकि डिजिटल इंडिया का सपना साकार किया जा सके।

साइबर खतरे :–

वर्तमान में डिजिटल लेनदेन व ऑलनाइन खरीददारी बढ़ती जा रही है साथ ही साइबर अपराध भी बढ़ने लगे हैं। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की निजी व गोपनीय जानकारी का गलत प्रयोग करने में, उनमें फेरबदल करने में व बैंक खाते से पैसे चुराने में किया जाता है। साइबर अपराध के लिए कई मनोवैज्ञानिक तरकीबें जैसे फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग का प्रयोग किया जाने लगा है।

अवसर :–

कर संग्रह में बढ़ोतरी :–

कर सरकार की आय का एक स्त्रोत है। नकदी रहित लेनदेन के कारण लेनदेन के वितरण के कारण अधिकतर लोग करदेयता के दायरे में आयेंगे जिससे करदाता की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे राजस्व बढ़ेगा। कुछ वर्षों में कार्पोरेट और वैयक्तिक आयकर में सुधार हुआ है, बेहतर कर प्रशासन वर्षों से टी.डी.एस. के विस्तार प्रतिकर वंचन उपाय और प्रभावी कर प्रदाताओं के आधार में बढ़ोतरी ने प्रत्यक्ष कर उछाल में योगदान दिया। जीएसटी प्रशासन में अप्रत्यक्ष कर फाइल करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी से भी कर उछाल से सुधार हुआ है। 2019–20 के लिए 1.67 का बजटीय कर उछाल न केवल दीर्घकालीन औसत 1. 02 से अधिक है बल्कि 2018–19 पीए में वास्तविक उछाल के आकार के दोगुने से भी अधिक है।

महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा :–

देश में सम्पूर्ण विकास के लिए महिला पुरूष दोनों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तीकरण में महिलाओं की वित्तीय स्थिति व शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नकदी रहित लेनदेन के लिए महिलाओं को बैंक खातों की आवश्यकता होगी जिसमें वह अपनी आय व बचत को बैंकों में जमा करेगी जिससे उन्हें ब्याज की प्राप्ति होगी व उनकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा जो महिला सशक्तीकरण में योगदान देगा। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार सभी बचत खातों में महिलाओं के खाते लगभग 28 प्रतिशत थे और कुल खातों की संख्या 33.9 करोड़ थी। मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार शीर्ष 40 बैंकों और आरआरबी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का हिस्सा बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया। जो महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण में बड़ी तेजी को दर्शाते हैं।

संकट के समय उपयोगी :–

नकदी रहित लेनदेन का महत्व अचानक से आये संकट जैसे बिमारी, दुर्घटना में कई अधिक बढ़ जाता है। डिजिटल माध्यमों से हम दूर से भी अपने घर परिवार की वित्तीय सहायता कर सकते हैं। हाल ही

में आयी कोविड–19 जैसी महामारी के समय डिजिटल लेनदेन के माध्यम से लोगों ने अपने घर–परिवार की वित्तीय सहायता की। इसके अलावा सरकार ने कोविड–19 के दौरान 42 करोड़ व्यक्तियों को सीधे नकद हस्तांतरण, 20 करोड़ से अधिक महिला जनधन खातों, भवन निर्माण व निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की, जिससे सरकार की लोगों तक पहुँच में सुधार हुआ। इस प्रकार डिजिटल माध्यमों से लेनदेन ने स्थिति को संभालकर रखा नहीं, तो परिस्थितियाँ और भी भयावह हो सकती थी।

निष्कर्ष :–

वर्तमान युग डिजिटल लेनदेन का युग है। प्रत्येक देश अपने देश को विकास के पथ पर आगे रखने के लिए नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार का लेनदेन न केवल व्यक्ति व व्यवसायिक संस्थानों के लिए ही उपयोगी है बल्कि सरकार भी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना बिचौलियों के सीधे जनता तक आसानी से पहुँचा रही है। साथ ही नकदी रहित लेनदेन से करवंचन को वित्तपोषण में कमी आती है, साथ ही करवंचन से राजस्व में वृद्धि सरकार के आय में वृद्धि कर देती है और जनकल्याण को बढ़ावा मिलता है।

सन्दर्भ सूची :–

- Sahu G.P., Singh Naveen Kumar (Oct. 2017) DOI 10.1007/978-3-319- 68557-1-40 Conference : Conference on Business, E-Services and Society.

  grahu@mnnit.ac.in

  "Parajigm shift of Indian Based Economy to cashless Economy : A study on Allahabad City.

- Diksha Ahuja "Cashless Economy in India" 2018 Pramana Research Journal ISSN No., 2249-2976 Volume 8 issue 2018.

- RBI Vision document.

- Economic Survey 2021-21.